

DROUGHT PRONE AREA

सामान्यतः वैंसा क्षेत्र जहाँ—

- I) 60 से.मी. से कम वार्षिक वर्षा होती है
- II) सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है,
- III) वर्षा की मात्रा आवश्यकता से कम हो सके
- IV) वर्षा की अपर्याप्त मात्रा भी अनियमित एवं अनिश्चित हो,

सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। (The area in India

where — (i) there occurs less than 60 cm as annual rainfall (ii) there is insufficient development of irrigation means (iii) rainfall is always scanty and (iv) scanty rainfall become indefinite and irregular is commonly known as drought prone area."

सूखा एक संकटापन्न स्थिति होती है जो वर्षा की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार — "सूखा कम से कम लगातार 22 दिनों की एक अवधि है जहाँ किसी भी दिन 25 मि.मी. (0.01 इंच) से अधिक वर्षा नहीं होती।"

① यह परिभाषा सम्पूर्ण भारतवर्ष पर लागू नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से 60 से.मी. से वार्षिक वर्षा दर्ज करने वाला क्षेत्र जिसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता 25% से अधिक होती है भारत का सूखा ग्रस्त (प्रवण) क्षेत्र कहलाता है।

② वैंसा क्षेत्र जहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता 20 से 60 प्रतिशत के बीच होती है चिरकालिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। जैसे — राजस्थान, पंजाब, पूर्वी

गोवाण्डा कृषि मंत्रालय के अनुसार — "एक सूखा प्रवण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ सूखा की संभावना 20% से अधिक होती है।"

"एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र वह होता है जहाँ सूखा की संभावना 40% से अधिक होती है और एक सूखा वर्ष तब धरित होता है जब औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम दर्ज होती है।"

सिंचाई विभाग के अनुसार : "वैंसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 100 mm से कम हो, वर्षा की अनिश्चितता 25% से कम हो, सिंचाई की सुविधा कुल कृषिगत क्षेत्र के अधिकतम 30% भाग पर ही हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है।"

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वैंसा क्षेत्र में

- 1) सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर — सामान्य सूखा
- 2) 25% से 50% वर्षा की कमी होने पर — मध्यम सूखा
- 3) 50% से अधिक वर्षा की कमी होने पर — भयंकर सूखा उत्पन्न होता है।

सूखा के प्रकार :

Meteorological Drought	Hydrological Drought	Agricultural Drought or Soil-Water Drought	Ecological Drought
मौसम विज्ञान संबंधी सूखा	जलवैज्ञानिक सूखा	कृषि व मृदा-जल सूखा	पारिस्थितिकीय सूखा
जब वर्षा की मात्रा ही काफ़ी कम हो	जल के स्रोतों के सूखने एवं भूमिगत जल स्तर के गिरने से पड़ने वाला सूखा	मिट्टी में नमी के घटने व मिट्टी में नमी-धारण क्षमता घटने से फलस्वरूप पड़ने वाला सूखा।	पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी आती है इसे Ecological Drought कहते हैं।
• 25-50% कम होने पर सामान्य सूखा • 50% से अधिक कम होने पर भीषण सूखा।			

भारत में सूखा :

भारत में ६० पर सौ मौनबून के कमजोर होने से सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्य से कम वर्षा पड़ने अथवा अपने निश्चित समय से देर से आने के कारण भारत में कहीं न कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में औसतन ५ वर्षों में एक बार सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। १८७७ ई. से लेकर १९८७ ई. तक भारत में २३ बार सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई।

मौसमी खण्ड (Meteorological Divisions)	
१) असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	१५ वर्षों में एक बार
२) बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कोकण एवं तटीय आन्ध्र प्रदेश	५ वर्षों में एक बार
३) पं. उ. प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, मराठवाड़ा	४ वर्षों में एक बार
४) तमिलनाडु, कर्नाटक	३ वर्षों में एक बार
५) पं. राजस्थान, गुजरात (A.P.), तेलंगाना (A.P.)	५ वर्षों में एक बार

सूखा के प्रमुख कारण — स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों के अन्धाधुंध कोटने, जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिक विकास के कारण हमारा पारिस्थितिकी संतुलन काफी हद तक बिगड़ गया। वर्षा काफी अनियमित एवं अनिश्चित होने लगी, जल स्रोतों का जलस्तर निम्न हो गया। रासायनिक खादों के अधिकाधिक प्रयोग से मिट्टी की उपर्युक्त के साथ-साथ नमी धारण करने की क्षमता घटने लगी। फलतः सूखा का प्रकोप काफी अधिक बढ़ गया।

भारत में सूखा वर्ष :

(१) सन् १९६६, १९६८, १९७३ तथा १९७९ ई. में देश को भयंकर सूखा का सामना करना पड़ा। १९६६ के सूखे का असर बिहार में लगभग १० लाख लोगों पर पड़ा। बिहार में लगभग ४०% फसल नष्ट हो गई। चारा के अभाव में लाखों पशुओं की मृत्यु हो गई। १९६८ ई. में राजस्थान सूखा की भीषण चपेट में आ गया जिसका प्रभाव यहां के २३ जिलों पर पड़ा जिसमें १०७३ गांव स्वप्रभावित हुए। १९७२-७३ की सूखा और भी अधिक भयंकर हुआ जिसकी चपेट में

(3) Drought prone Areas

राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के विस्तृत क्षेत्र आ गए। इस सूखा का प्रभाव लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों पर पड़ा। इसके कृषि क्षेत्र में 1558 करोड़ रुपये की हानि हुई। राज्य सरकारों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने राहत कार्यों पर 143 करोड़ रुपये खर्च किए।

सन् 1979 ई० में देश के 150 जिलों पर सूखा का प्रभाव पड़ा एवं 230 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन भी हानि हुई।

1980-90 के दशक में सूखा की विभीषिका और भी अधिक बढ़ गई। 1984-85 से 1987-88 तक देश को निरंतर सूखा का सामना करना पड़ा। 1985-86 ई० में देश के 7 राज्यों, 1985-86 में 10 राज्यों तथा 1986-87 ई० में 17 राज्यों में सूखा पड़ा। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि 1987 का सूखा 20वीं सदी का सर्वाधिक भयंकर सूखा था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भारत के 35 जलवायु खण्डों में से 25 में वर्षा सामान्य से कम हुई। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत के तत्कालीन 470 जिलों में से केवल 145 जिलों में ही सामान्य वर्षा हुई शेष 325 जिले भयंकर सूखा की चपेट में रहे। गुजरात, आन्ध्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जार्खण्ड, राजस्थान में सूखा का भयंकर प्रभाव पड़ा। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार - इस सूखा से 20 अरब रुपये से अधिक कृषि उपज का प्रत्यक्ष हानि हुई। इसके अतिरिक्त 55 अरब रुपये राज्य सरकारों तथा 20 अरब रुपये केन्द्र सरकार ने सूखा राहत के लिए खर्च किए।

1998-2001 की अवधि में गुजरात तथा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई एवं पशुजल की काफी कमी हो गई। आरों संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले गए।

2002-2009 की अवधि के दौरान भी देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति पैदा हुई लेकिन यह सूखा साधारण था फलस्वरूप लोगों में बचैनी कम रही और इसका कम आर्थिक भार सरकारी खजानों पर पड़ा।

2010-11 में तो स्थिति सामान्य बन ली गई लेकिन मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान में आंशिक सूखा का असर अवश्य दिखा।